



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/ माघ 28, 1938

No. 45]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

**विषय :** चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के मूल के या वहां से निर्यात किए गए “विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा.सं. - 14/34/2016-डीजीएडी (प्रकरण संख्या - OI/08/2017).**—जबकि, मै. ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लि. (जिसे आगे ‘आवेदक’ कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे ‘प्राधिकारी’ भी कहा गया है) के समक्ष समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ‘नियमावली’ भी कहा गया है) के अनुसरण में विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग (जिसे आगे ‘संबद्ध वस्तु’ भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है। ऊपर उल्लिखित देशों को भी “संबद्ध देश” कहा गया है।

**क. पाटित किया जा रहा उत्पाद और समान वस्तु:**

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि वर्तमान अधिसूचना में शामिल किए गए देशों से विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार की फ्लोरिंग को शामिल किए बिना “विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग” का पाटित मूल्यों पर भारतीय बाजार में आयात हो रहा है और ऐसे आयात समान उत्पाद वाले घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन रहे हैं-

- (क) लेमिनेटिड फ्लोरिंग
- (ख) लकड़ी के बिना बनी फ्लोरिंग
- (ग) विनियर्ड टॉप लेयर न रखने वाली फ्लोरिंग
- (घ) ठोस वुड फ्लोरिंग

3. ऊपर उल्लिखित उत्पाद को वर्तमान अधिसूचना में “विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग” या विचाराधीन उत्पाद के रूप में संदर्भित किया गया है। विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग में विशेष रूप से लकड़ी की तीन परतें अर्थात् “टॉप लेयर”, “मिडिल लेयर” और “बॉटम लेयर” होती है। टॉप लेयर असली लकड़ी है जो पूरे निर्माण को आकर्षक रूप (इसकी लकड़ी की संरचना होने के कारण) और अतिरिक्त मजबूती देता है। यह लकड़ी की एक पट्टी, दो पट्टी या तीन पट्टियों से बना हो सकता है। मिडिल लेयर असली लकड़ी है जो समग्र निर्माण का केंद्र है। वह या तो “ठोस लकड़ी” या “फाइबर बोर्ड” का बना हो सकता है। बॉटम लेयर असली लकड़ी है जो समग्र निर्माण को सहारा देती है।

4. विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग एक असली वुड उत्पाद है। लकड़ी की टॉप लेयर जिसके विनियर्ड की रेंज 0.5 मि.मी. से 6 मि.मी. के बीच की मोटाई की है। कुल मिलाकर बोर्ड की मोटाई की रेंज 8 मि.मी. से 25 मि.मी. की है। इसके मल्टीप्लाई ढांचे के कारण इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग ठोस वुड की तुलना में अधिक उपयुक्त है और तापमान व आर्द्रता में परिवर्तन के साथ सिकुड़ने और फैलने के प्रति कम संवेदी है।

5. उपर्युक्त उत्पाद को आमतौर पर विशिष्ट मानक आकारों और विशिष्टताओं में उत्पादित और बेचा जाता है। तथापि, उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए इसे विभिन्न आकारों में उत्पादित किया जा सकता है। विभिन्न उत्पाद प्रकारों के आकार और विशिष्टताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 44 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के सीमाक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशेषताएं, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों को विनिर्माण कर सकते हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और अतः इन्हें नियमों के तहत ‘समान वस्तु’ रूप में माना जाएगा। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे संबद्ध सामान के “समान वस्तु” के रूप में माना है।

#### ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. आवेदन मै. ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लि. (घरेलू उद्योग के रूप में संदर्भित या वर्तमान अधिसूचना में ‘आवेदक’) द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं। आवेदक कथित पाटित वस्तुओं के निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने स्वीडन (ई.यू.) एक गैर-संबद्ध देश, से संबद्ध वस्तुओं की नगण्य मात्रा का आयात किया है जो भारत में मांग/आपूर्ति, भारत में कुल आयात, आवेदक द्वारा स्थापित क्षमता और जांच की अवधि के दौरान इसके कुल उत्पादन की शर्तों में नगण्य है और इसके विवरण आवेदन के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। प्रकरण के तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि आवेदक को नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

9. आवेदक पात्र घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 100% हिस्सा रखते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियम 2(ख) में यथा परिभाषित अर्थ के दायरे के भीतर घरेलू उद्योग है। उनका संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में भी

प्रमुख हिस्सा है अतः नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में आवेदन दायर करने की योग्यता रखते हैं। अतः आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा ओर उसकी ओर से किया गया माना जाता है।

#### ग. जांच किए जाने वाले देश

10. वर्तमान जांच चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ ('संबद्ध देशों' के रूप में ज्ञात) से विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग के कथित पाटित आयातों के संबंध में है। इन देशों से आयातों की मात्रा विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है। उक्त देशों के अलावा लिथुआनिया से भी न्यूनतम सीमा से अधिक आयात हुए हैं। तथापि, ये आयात काफी अधिक कीमतों पर हैं।

#### घ. पाटन का साक्ष्य

11. याचिकाकर्ता ने बताया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान उन देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की प्रचलित कीमतों पर विचार करते हुए उत्पादन लागत, सबसे अधिक कार्यकुशल घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और विधिवत रूप से समायोजित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय जमा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए लगाया गया है।

12. आवेदक ने निर्यातित संबद्ध वस्तु की निवल कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विसेस (आईबीआईएस) से प्राप्त सौदों एवं आयात आकड़ों के आधार पर दावा किया है जो एक द्वितीय स्रोत, जांच की अवधि के लिए है जिसमें समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभार और वैट समायोजन, (केवल चीन जन.गण. के लिए) लागू हो को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

13. निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से पता चलता है कि इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात सामान्य मूल्यों से काफी अधिक कीमतों पर किया जा रहा है और पाटन मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक है।

#### ड. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से उल्लेखनीय क्षति हुई है जैसा कि विभिन्न मापदंडों द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कुल रूप में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि, मूल्य ह्रास, कम कीमत पर बिक्री और मूल्य तालिका, लाभदायिकता, नियोजित पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह पर परिणामी विपरीत प्रभाव पड़ना। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि विचारधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग की स्थापना को पर्याप्त रूप से धीमा किया है। देश में उत्पादन की मांग पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार में हिस्सा काफी निम्न है और यह विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ने कुछ समय पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था। अतः पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित बताने के लिए संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही 'क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

#### च. जांच की शुरुआत

15. और यतः उक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरुआत करते हैं।

**छ. जांच की अवधि (पीओआई)**

16. इस जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अक्टूबर, 2015 से सितंबर, 2016 तक है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच अवधि के आंकड़े शामिल होंगे।

**ज. सूचना प्रस्तुत करना**

17. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योगों को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में व ढंग से संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें जिससे प्राधिकारी समयबद्ध ढंग से समुचित निर्धारण कर सकें:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य विभाग,**  
**चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**  
[www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

**झ. समय सीमा**

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस (40) दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर और तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड प्रति साथ ही सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को इस सूचना के पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर अपने उत्तर अलग-अलग प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग सूचित किया जा रहा है।

21. वर्तमान जांच और सुनवाई से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच सके। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करा सकते हैं।

22. यह नोट किया जाए कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज करा सकते हैं।

**ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय आधार पर प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा। जिसे अन्य हितबद्ध पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी मूल प्रति के साथ दो-दो (2) प्रतियों में दोनों अंशों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

24. दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

25. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता व्यापार संवेदी सूचना होने का दावा करता है जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना के प्रदाता को वाणिज्यिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे। ऐसी सूचना जिसे स्वरूप द्वारा गोपनीय होने का दावा किया जाता

है या अन्य कारणों से जिसका गोपनीय होने का दावा किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से गोपनीय और गोपनीय होने के दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों के विवरण प्रस्तुत करने होंगे कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **ड. असहयोग**

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 17th February 2017

#### **INITIATION NOTIFICATION**

**Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Veneered Engineered Wooden Flooring” originating in or exported from China, Malaysia, Indonesia and European Union.**

**F.No.14/34/2016-DGAD (Case No. – OI/08/2017).**— Whereas, M/s. Greenlam Industries Limited (hereinafter referred to as “the applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as

“the Rules”) for imposition of anti-dumping duty on imports of Veneered Engineered Wooden Flooring (also referred to as “the Subject goods”). The Countries concerned are China, Malaysia, Indonesia and European Union. The above mentioned countries are also referred to as “the Subject Countries”.

**A. Product allegedly being dumped and like Article**

2. The applicant have alleged that the imports of "Veneered Engineered Wooden Flooring" specifically excluding following kind of floorings from the countries named in the present notification are entering the Indian market at dumped prices and such imports are causing injury to the like product domestic industry.

- (a) laminated flooring,
- (b) flooring not made of wood,
- (c) flooring not having veneered top layer ,
- (d) solid wood flooring

3. The above mentioned product has been referred as “Veneered Engineered Wooden Flooring” or product under consideration in the present notification. Veneered Engineered Wooden Flooring typically has three layers of wood viz “Top Layer”, “Middle Layer” and “Bottom Layer”. Top Layer is real wood which gives attractive look (owing to its wooden texture) and additional strength to overall construction. It can be made of one strip of wood, two strips of wood or three strips of Wood. Middle Layer is real wood, which forms core of the overall construction. It can be made of either “solid wood” or “fibre board”. Bottom Layer is real wood which provides support to the overall construction.

4. Veneered engineered wooden flooring is a real wood product. The top layer of wood called the veneer ranges from 0.5 mm to 6 mm thickness. Overall board thickness ranges from 8 mm to 25 mm. Due to its multiply structure the engineered wooden flooring is more suitable than solid wood and is less susceptible to shrinking and expanding with changes in temperature and humidity.

5. The above product is normally produced and sold in certain standard sizes and specifications. It can, however, be produced in different sizes to meet the requirements of customer. Different product types can be categorized on the basis of sizes and specifications.

6. The product under consideration is classified under Chapter 44 of the Customs Tariff Act. The customs classification above is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in this investigation.

7. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. For the purpose of the present investigation, the Authority has treated the subject goods produced by the domestic industry in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

**B. Domestic Industry & Standing**

8. The application has been filed by M/s. Greenlam Industries Limited (referred to as “the Domestic Industry” or “the applicant” in the present notification). There are no other producers of the subject goods in India. The applicant is not related to the exporters or importers of the alleged

dumped article. The applicant has imported insignificant volume of subject goods from Sweden (EU), a non-subject country, which are negligible in terms of demand/consumption in India, total imports into India, capacity set up by the applicant and its total production during the period of investigation and the details of the same have been provided with the application. The facts of the case clearly establish that applicant should be considered eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

9. The applicant, commanding 100% of the total production of the eligible domestic production, constitute the domestic industry within the meaning of the term as defined in Rule 2(b) for the purpose of present investigation. They also account for a major proportion of the domestic production of the subject goods and therefore, command the standing to file the application in terms of Rule 5(3) of the Rules. Therefore, the application is deemed to have been made by and on behalf of the domestic industry.

**C. Countries to be investigated**

10. The present investigation is in respect of alleged dumped imports of Veneered Engineered Wooden Flooring from China PR, Malaysia, Indonesia and European Union(referred to as “the subject countries”).The volume of imports from these countries is above the de-minimis limit prescribed. Apart from the above countries, volume of imports from Lithuania is also above de-minimis limits. However, these imports are at significantly higher prices.

**D. Evidence of Dumping**

11. The applicant has submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the normal values in the subject countries have been estimated on the basis of estimates of cost of production, taking into account prevailing prices of raw materials and utilities in those countries, conversion costs of the domestic industry, and duly adjusted to include selling, general & administration expenses, and a reasonable profit.

12. The applicant has claimed ex-factory export price on the basis of transaction wise import data procured from International Business Information Services(IBIS), a secondary source, for the period of investigation and after due adjustments on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges and VAT adjustment (only for China PR).

13. The normal values and export prices determined show that there is sufficient prima facie evidence that the subject goods are being exported from the subject countries to India at a price significantly higher than normal value and the dumping margins are above de-minimis.

**E. Evidence of Injury and Causal Link**

14. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports as shown by various parameters such as significant increase in imports in absolute terms, price depression, price underselling and consequent adverse impact on inventories, profitability, return on capital employed, and cash flow of the domestic industry. The applicant has also claimed that dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry is quite low considering the demand for the product in the Country and considering that the domestic industry commenced commercial production sometime back. There is

sufficient prima facie evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping Investigation.

**F. Initiation of the Investigation**

15. Having regard to the above Rules, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

**G. Period of Investigation (POI)**

16. The period of investigation for the purpose of present investigation is from October 2015-September 2016. However, the injury investigation period covers the data of previous three years, i.e. 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.

**H. Submission of information**

17. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address, so as to enable the Authority make appropriate determinations in a timely manner:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001  
dgad.india@gov.in**

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the Authority at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) within the time limit set out below.

**I. Time limit**

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 2 weeks from the date of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.



20. The exporters/importers and other interested parties, being notified individually may file their responses within forty days (40 days) from the date of the letter of intimation to be addressed to them separately.

21. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

22. It may be noted that if no information is received from an interested party within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the Rules.

**J. Submission of Information on Non-Confidential basis**

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority, including questionnaire response on confidential basis, are required to file a non-confidential version of the submissions made, which will be made available to all other interested parties to make their comments. Soft copies of both the versions are required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked so at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

25. The confidential version may contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as business proprietary information, disclosure of which will adversely affect the commercial interests of the supplier of such information. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out. In case indexation is not feasible, the information may be summarized, depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is

not warranted, or if the supplier of the information is either not willing to make the information public, or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**K. Inspection of Public File**

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties to the investigation.

**L. Non-cooperation**

29. In case, any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority